

**Statement  
Facilities to Haj Pilgrims**

1. The Government of India permit issue of foreign exchange worth Rs. 1575.00 per adult to the Haj pilgrims.
2. Foodgrains and sugar are supplied to the pilgrims at controlled rates and they are allowed to carry these up to a prescribed quantity for their consumption during their stay in Saudi Arabia.
3. A Medical Mission composed of 10 doctors and 10 compounders is deputed every year to Saudi Arabia to render medical assistance free of charge to Indian pilgrims who go to Saudi Arabia during Haj.
4. Small dispensaries are opened up at various places in Jeddah, Mecca and Medina to give free medicines to the sick pilgrims. A mobile medical unit also operates for treating emergency cases.
5. Shaboels are installed at various places in Saudi Arabia for providing cold drinking water to the pilgrims.
6. The Officers and the staff of the Indian Embassy in Jeddah are deputed to render all possible assistance and guidance to the Hajis.
7. The Railway authorities open temporary offices in Saboo Siddique Musafirkhana, Bombay for issuing tickets to Hajis for their homeward journey.
8. The Reserve Bank of India open a Branch Office in the premises of the Saboo Siddique Musafirkhana for issuing foreign exchange to the Haj pilgrims.

**मध्य प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास**

8680. श्री राम सिंह अयरवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र का आधा भाग मध्य प्रदेश में तथा आधा भाग उत्तर प्रदेश में है और उक्त क्षेत्र मुख्य रूप से डाकूप्रस्त क्षेत्र है और झांसी, जालोन, ललितपुर आदि जिलों को मध्य प्रदेश में शामिल किए जाने से डाकूओं की समस्या को हल करने में पुलिस को सहायता मिलेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाकूप्रस्त होने के कारण इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास नहीं किया जा सकता ।

(ग) क्या संचार साधनों के अभाव के कारण उक्त क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है ;

(घ) क्या उक्त समस्या के हल के लिए सरकार इस क्षेत्र में खर्च करने के लिए कुछ विशेष धन की व्यवस्था करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस समस्या को हल करने में क्या कठिनाइयाँ हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अशुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) में (ङ). अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र की सामाजिक घटनाएं भी इसकी अर्थ व्यवस्था और अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में उद्भूत हुई हैं। इस क्षेत्र को डाकूओं के संकट से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श में कुछ उपायों की जांच की जा रही है। इनमें सड़क संचार का विकास भी शामिल है। किसी क्षेत्र में उद्योग की स्थापना तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता, कच्चे माल की उपलब्धि आदि पर आश्रित है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दें।

अन्वमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में भूतपूर्व सैनिकों को रिहायशी प्लॉटों तथा खेती योग्य भूमि का दिया जाना

8681. श्री हुसम चन्द कछवाय : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) अन्वमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कितने भूतपूर्व सैनिकों को रिहायशी प्लॉट तथा खेती योग्य भूमि दी गई है ; और